



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 1991/माघ 10, 1912  
No. 46] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 1991/MAGHA 10, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1991

सा.का.नि. 54 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित  
उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :—

यतः मेरा, भारत के राष्ट्रपति, भार. केकरामन, का यह समाधान  
हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तमिलनाडु राज्य  
का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संविधान'  
कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

अतः, अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का  
तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का  
प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं :—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के  
राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ,  
भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता हूँ ;

(ख) भीक्षित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधानमंडल की  
शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन  
प्रयोक्तव्य होंगी ; और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूँ  
जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए  
मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं ; अर्थात् :—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खण्ड (क) के आधार  
पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का  
प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के  
रूप में उस सीमा तक जितना तक मैं ठीक समझूँ  
उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना  
विधिपूर्ण होगा ;

(ii) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित  
उपबंधों के प्रवर्तन की एतद्वारा मिलान किया  
जाता है, अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति  
द्वारा राज्य के विधानमंडल की निदेश करने से है ;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत  
के नियंत्रक, एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल की प्रस्तुत की गई रिपोर्ट  
के राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

अनुच्छेद 163 और 164 ;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध  
राज्य सरकार के कार्यों का संवित्तियों के बीच बाँटन से है ;

अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प के पारित किए जाने से है ;

अनुच्छेद 174 का खंड (1), और गण (2) का उपखंड (ग) ;

अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 179 का खंड (ख) और (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक, और अनुच्छेद 180 और 181 ;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा ने उपाध्यक्ष के संसदों और अर्थों से है ; अनुच्छेद 188, 189, 193, 194, 195 तथा 196 ;

अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4) ;

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबन्धों और भक्तों से है ; अनुच्छेद 208 न 211 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) अनुच्छेद 213 का खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक ; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध आपन संहिता रिपोर्ट की राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

(iii) उक्त राज्य का विधान सभा एतद्वारा संग की गयी है ;

(iv) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के विधान मंडल के प्रति किसी निदेश का, जहाँ तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उनकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ में राज्यपाल पर्यवेक्षित न हो, संगद के प्रति निदेश लगाया जाएगा, और विनिश्चितता अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा ;

परन्तु इसमें कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 में लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से 4 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) के उल्लंघनों पर प्रभाव नहीं डालेगी अथवा राष्ट्रपति को इस खंड के उपखंड (1) के अंतर्गत उस सीमा तक जहाँ तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के भाषण में कार्य करने में विचारित करेगा,

(v) संविधान में उक्त राज्य के विधान मंडल के या एतद्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत इस उद्घोषणा के अन्तर्गत पर संसद द्वारा, राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) में निश्चित अन्य प्राधिकारी द्वारा उक्त राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियम या विधियों के प्रति निदेश है, और तत्पश्चात् साधारण खंड अधिनियम, 1891 (1891 का तमिलनाडु अधिनियम 1), वैसाकि वह तमिलनाडु राज्य में लागू है, और साधारण खंड अधिनियम 1897 (1897 का 10) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में

ऐसे प्रभावहीन होगा मानो वह उक्त राज्य विधानमंडल का अधिनियम हो ।

नई दिल्ली,  
30 जनवरी, 1991

आर० वेंकटरामन,  
राष्ट्रपति

[फा.सं. V/11013/2/91-7. इस राज्य

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 1991

G.S.R. 54(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas, I, R. Venkataraman, President of India, am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Tamil Nadu cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I —

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely :—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State.

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely :—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1), and sub-clause (a) of clause (2), of article 174; articles 175 to 178 (both inclusive) clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196; clauses (3) and (4) of article 199;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive), the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State shall be construed as references to the President and to Parliament; respectively :

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the said State shall be construed as including a reference to Acts or laws made in exercise of the powers of the Legislature of the said State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Tamil Nadu General Clauses Act, 1891 (Tamil Nadu Act 1 of 1891), as in force in the State of Tamil Nadu, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the said State.

New Delhi.

The 30th January, 1991.

R. VENKATARAMAN,  
PRESIDENT

[No. V/11013/2/91-CSR]

आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1991

सा.का.सि. 55 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्न-लिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनायें प्रकाशित किया जा रहा है :—

भारत के संविधान अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे उत्तर आज 1991 वर्ष के जनवरी, मास के तीसरे दिन जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (1) का अनुसरण करते हुए, मैं एतद्वारा निवेदन देता हूँ कि तमिलनाडु राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उक्त राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोज्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोज्य होंगी ।

नई दिल्ली,  
30 जनवरी, 1991

आर. वेङ्कटरामन,  
राष्ट्रपति

[क्र.सं V-11013/2/91-पी.एस.आर.]

आर के. मारीच, गह सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 30th January, 1991

G.S.R. 55(E).—The following Order by the President is published for general information :—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 30th day of January, 1991, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Tamil Nadu and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in

force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi.

The 30th January, 1991.

R. VENKATARAMAN,

PRESIDENT

-----  
[No. V/11013/2/91-CSR]

R. K. BHARGAVA, Home Secy.